उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा, इससे रोजगार पाने वालों में होगा भारी इजाफा

एमएसएमई बनेगा रोजगार का बड़ा जरिया

फायदा

अजित खरे

लखनऊ। इस बार रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली मोदी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने की कोशिश की है। चाहे वह मुद्रा योजना का विस्तार हो, या एमएसएमई इकाईयों को आसान व सस्ता कर्ज दिलाने की राह खोलना हो। इस मुहिम का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को होने जा रहा है। इसकी वजह है कि देश में सबसे ज्यादा 96 लाख सूक्ष्म, मध्यम व लघु इकाइयां यूपी में काम रही हैं। यह यूनिट अपने उद्योग विस्तार के लिए आसानी से कर्ज पा सकेंगी। स्वरोजगार करने के लिए करोड़ों युवाओं को अब आसानी से कर्ज लेने का रास्ता खुलेगा। असल में यूपी सरकार ने वार्षिक ऋण योजना के तहत 2024-25 के लिए लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले डेढ़ गुना बढ़ा दिया है। अब लक्ष्य 5.18 लाख करोड़ रुपये का है। इन नए ऐलानों से इस लक्ष्य को पाने में आसानी होगी।

01.65

करोड़ लोग सूक्ष्म, मध्यम और लघु इकाइयों से पा रहे हैं रोजगार

यूपी को काफी फायदा होगा: प्रमुख सचिव

यूपी के एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार का कहना यूपी का एमएसएमई सेक्टर उद्योगों की संख्या व रोजगार के लिहाज से सबसे आगे है। निर्यात में भी इस सेक्टर की हिस्सेदारी देश में सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत है। बजट में आए सभी प्रावधानों का यूपी भी बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए योजनाओं का प्रभावी अमल कराएगा। रोजगार के लिहाज से यूपी के इस सेक्टर को काफी फायदा होगा।

मुद्रा योजना के जरिए अब उद्यमी लगा सकेंगे बड़े प्रोजेक्ट : केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना में 10 लाख की सीमा को बढ़ा कर 20 लाख कर दिया है। अब जिन्होंने अपना पुराना लोन अदा कर दिया है वह इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यूपी में पिछले साल तक 6808721 लोगों ने 48194.89 करोड़ का कर्ज लेकर इस योजना का लाभ उठाया। अब यह उद्यमी बड़े प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। मुद्रा योजना की खासियत है कि इसमें कर्ज बहुत आसानी से मिल जाता है।

जिन इकाइयों का टर्नओवर 500 करोड़ है को अनिवार्य रूप से ट्रेडर्स (TReDS) प्लेटफार्म पर पंजीकरण करना होता है। अब इसकी सीमा 250 करोड़ कर दी गई है। इससे इकाइयों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा। इससे देश भर की 7000 से अधिक कंपनियां एक प्लेटफार्म पर पंजीकृत हो पाएंगी। अभी यूपी में इस प्लेटफार्म पर आनबोर्ड आने वाली कम ही कंपनियां हैं। टर्नओवर सीमा घट जाने से यूपी में अब यह संख्या बढ़ेगी।

12 औद्योगिक क्लस्टर में कम से कम दो यूपी चाहेगा : सचान

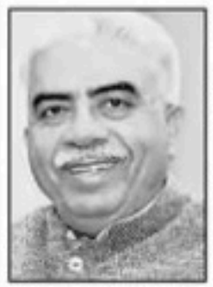

मंत्री ने कहा, राज्य में सिडबी 24 नई शाखाएं खोलेगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने आम बजट 2024-25 को एक सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बजट बताया। कहा कि बजट में 12 इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान हुआ है। यूपी चाहेगा कि कम से कम दो पार्क इस राज्य में आएं। इसके लिए यूपी सरकार विशेष प्रयास करेगी। राकेश सचान ने कहा कि एमएसएमई क्लस्टर्स में अगले तीन वर्षों में सिडबी की 24 नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी। देश की 500 बड़ी कंपनियों में अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।